है) यूनिटों को चालू करने की इस समय आशयित तिथियां निम्नलिखित हैं :—

(1) 15 मैगावाट यूनिट मार्च/अप्रैल, 1966

(2) पहली 62.5 यूनिट सितम्बर/अक्टूबर, 1966

(3) दूसरी 62.5 यूनिट फरवरी, 1967

(4) तीसरी 62.5 यूनिट अप्रैल, 1967

(ख) अभी तक दिल्ली प्रशासन ने ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया है । फिर भी, दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम लघु उद्योगों के लिये बिजली की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने की आशा रखता है ।

कानपुर और जालौन में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

306. **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उन मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, जिनके सम्बन्ध में आयकर अधिकारियों द्वारा जालौन तथा कानपुर, में 23 और 24 नवम्बर, 1965 को छापे मारे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) पूछ-ताछ अभी भी जारी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अस्पताल

307. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों में रोगियों को दवा आदि लेने में कई घण्टे लग जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियां

308. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा इसके आस पास के क्षेत्रों से गन्दी बस्तियों को कब तक हटाने का सरकार का इरादा है ; और

(ख) ऐसी बस्तियों की संख्या कितनी है और ये कहां कहां है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) कोई अनुमान देना कठिन है । यह निर्भर करेगा (क) उन क्षेत्रों के मालिकों के सहयोग पर जो कि गन्दी बस्तियों के विकास और सफाई के क्षेत्रों के है ; (ख) जिन स्थानों पर इस समय गन्दी बस्तियों के रहने वाले रह रहे हैं उन स्थानों से दूसरे स्थानों पर जाने की उनकी इच्छा पर ; (ग) शहर के

बाहर भूमि उपलब्ध होने पर ; तथा (घ) निधियों के नियतन पर ।

(ख) दिल्ली की गन्दी बस्तियां इन क्षेत्रों में हैं :—

(1) दिल्ली नगर निगम के वार्ड न० I से XX तक ।

(2) मल्कागंज रोड, बोलवड रोड, रिज, पुरानी नोटीफाईड एरिया कमेटी की सीमा, सिविल स्टेशन के अन्दर, मोरी गेट के बाहर का क्षेत्र ।

(3) कोटला मुबारकपुर ।

(4) वाल्मीकी मंदिर तथा रीडिंग रोड पुलिस स्टेशन के पीछे रिज रोड पर हरिजन बस्ती ।

(5) कुशक नाला के साथ पिलन्जी गांव, मेन विनय नगर के सामने "जेड" ब्लाक ।

(6) सब्जी मंडी के नजदीक गुड़ की मंडी तथा राजपुरा गांव ।

(7) वर्मा जर्मोल–शाहदरा–दिल्ली ।

(8) पश्चिमी रोहतास नगर का क्षेत्र तथा रेहमान बिल्डिंग के पीछे की भूमि, शाहदरा–दिल्ली ।

(9) सुदामा पुरी, नजफगढ़ रोड ।

(10) साउथ गांधी नगर, शाहदरा–दिल्ली ।

Finance Commission's Allocations

309. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Calcutta issue of the *Statesman* dated the 23rd December, 1965 under the heading "Finance Commission's allocation unfair, State efforts explained";

(b) whether the Bihar Finance Minister told the Bihar Assembly on the 20th December, 1965 that the Fourth Finance Commission's allocation of Rs. 197·5 crores to the State from the Central pool during the next five years was 'unfair'; and

(c) whether the Central Government have taken any steps to satisfy the Bihar Government?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) No Sir. The Calcutta City edition of the *Statesman* dated the 23rd December, 1965 does not contain any such news-item.

(b) An authentic copy of the Bihar Finance Minister's speech is awaited from the State Government. They have, however, informed the Government of India that although no statement as such was made by the Minister, a reference to the Finance Commission's award and its general effect on Bihar was made during the debate on the excess grants.

(c) The Government of India have not received any representation in the matter from the Government of Bihar. The Finance Commission's recommendations are treated as an award and there is therefore no question of taking any steps to satisfy any State Government.

C.H.S. Doctors

310. **Shri Hem Raj:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) how far the observance of the "work to rule" by the doctors of the C.H.S. affected the care of the patients;

(b) how many patients they were looking after before the strike and how many after the strike; and